>

Title : Need to include Chandauli and Mirzapur districts of Uttar Pradesh in Integrated Action plan for Naxal-hit districts in the country.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): देश के विभिन्न राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों (चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र) में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा नक्सल इंटिग्रेटेड एक महत्वपूर्ण योजना (तेरह हजार तीन सौ निन्यानवे करोड़ रूपये) का प्रावधान मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद को तो सम्मिलित किया गया और चन्दौली, मिर्जापुर जनपदों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। पूरे देश के पैंतीस जनपद इस महत्वपूर्ण योजना में सम्मिलित हैं। इनके लिए सम्मिलित करने के भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो मानक बनाए गए हैं, उस मानक के आधार के अनुसार जनपद चंदौली और मिर्जापुर पूरी तरह से नक्सल प्रभावित विशेष जनपदों की श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में कई नक्सली वारदातें और घटनाएं घटित हो चुकी हैं। दो दर्जन से अधिक पुलिस, पीएसी के जवान शहीद हो चुके हैं तथा कई दर्जन आम नागरिक मारे गए हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डेटोनेटर, बारूदी विस्फोटक सामान एवं नक्सली पकड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली व मिर्जापुर जनपदों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की बड़े पैमाने पर कमी है। यहां पर सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार औद्योगिक विकास सहित पेयजल स्वास्थ्य सुविधायें स्कूल, कालेजों की कमी है। जिसके चलते गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, गंभीर बीमारी आदि समस्याओं से जनपद चंदौली एवं मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के जनपद जूझ रहे हैं। जनपद चंदौली को जिला घोषित किए दस वर्षों से अधिक समय हो चुका है, परन्तु अभी तक यहां जिला मुख्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों का निर्माण एवं अधिकारियों आदि की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अभी भी यहां का बहुत सा कार्य पुराने जनपद वाराणसी के अधिकारियों द्वारा संचालित होता रहता है। यह जनपद बिहार राज्य की सीमा एवं छत्तीसगढ़ तथा नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र व मिर्जापुर से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जनपद चंदौली और मिर्जापुर सहित दो-तीन जिलों को उपरोक्त योजना से सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है।

मेरी सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि जनपद चंदौली व मिर्जापुर को नक्सल इंटिग्रेटेड एक्शन प्लान में सम्मिलित करते हुए बुनियादी सुविधाओं हेतु विकास कार्यों को प्रारंभ करें।